ये केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार स्थापित किए गए हैं जो कि इस प्रकार है—

	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/ आदिवासी क्षेत्र
उप केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

1991 की जनगणना के अनुसार इन सुविधाओं की अपेक्षित तथा कार्यरत स्थिति इस प्रकार है—

स्वास्थ्य केन्द्र	अपेक्षित	दिसम्बर, 95 को कार्यरत
उप केन्द्र	134105	132285
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	22351	21802
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	5588	2401

इस अन्तर को जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार अतिरिक्त केन्द्रों द्वारा अथवा मौजूदा केन्द्रों में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था से सेवाओं का विस्तार करके दूर करने का प्रस्ताव है। यह कार्य 9वीं योजना में किया जाएगा।

(ख) सरकार ग्रामीण जनसंख्या को उल्लिखित स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले निवारक, उपचारात्मक, परिवार कल्याण सेवाएं तथा टीकाकरण सुविधाएं प्रदान कर रही है।

Product diversification programme of Haldia Refinery

*40. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any product diversification programme is being planned by Haldia Refinery of IOC, if so, the details thereof;

(b) whether any feasibility report has been prepared and examined by IOC for utilising the existing facilities of the Fertilizer Project of HFC, Haldia; and

(c) if so, whether the same involves production of Chemicals/Fertilizer by IOC, other than utilisation of infrastruc-tural facilities of Haldia Project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T. R. BAALU): (a) As a part of product diversification, Microcrystallinc wax production/despatch facilities are under implementation by IOC at Haldia Refinery. The project estimated to cost Rs. 35 crores is scheduled to be mechanically completed by April, 1999.

(b) and (c) IOC is exploring the feasibility of utilising some of the idle facilities of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. at Haldia.

गांवों का विद्युतीकरण

39. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने राजस्व ग्राम हैं और ऐसे कितने राजस्व ग्राम विद्युत विहीन हैं; और

(ख) इन ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) 31.3.1996 को उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में अभी 80,927 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ख) शेष गैर-विद्युतीकृत गांवों में से अधिकांश दूरस्थ, दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनके विद्युतीकरण के लिए बहुत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत बोर्डों से शेष गांवों का विद्युतीकरण पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान करने हेतु तथा आवश्यक कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

देश में बसे हुए विद्युतीकृत तथा गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या

		(31.3.1996 की स्थिति रिपोर्ट)		अनंतिम
क्र॰ सं॰	राज्य	बसे हुए गांवों की कुल संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	मार्च, 96 की स्थिति अनुसार विद्युतीकृत गांव (अनंतिम)	बसे हुए गांव, जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है (मार्च, 96 की स्थिति)
1.	आन्ध्र प्रदेश	27379	27358 **	
2.	अरूणाचल	3257	2270	987
3.	असम	21995	21887	108
4.	बिहार	67546	47805	19741
5.	गोवा	386	377 **	
6.	गुजरात	18114	17892 **	
7.	हरियाणा	6745	6745 **	
8.	हिमाचल प्रदेश	16807	16761 **	
9.	जम्मू और कश्मीर	6477	6252 *	225
10.	कर्नाटक	27028	26483 **	
11.	केरल	1219	1219 **	
12.	मध्य प्रदेश	71352	67741	3611
13.	महाराष्ट्र	39354	39016 **	
14.	मणिपुर	2035	2016	19
15.	मेघालय	4902	2407	2495
16.	मिजोरम	721	727 (+)	
17.	नागालैंड	1112	1099 **	
18.	उड़ीसा	46553	33429 (*)	13124
19.	पंजाब	12342	12342 **	
20.	राजस्थान	34968	30620	4348
21.	सिक्किम	440	405 **	
22.	तमिलनाडु	?15831	15822 **	
23.	त्रिपुरा+	856	3593 (*)	1134

		(31.3.1996 की स्थिति रिपोर्ट)		अनंतिम
क्र० सं०	राज्य	बसे हुए गांवों की कुल संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	मार्च, 96 की स्थिति अनुसार विद्युतीकृत गांव (अंनन्तिम)	बसे हुए गांव, जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है (मार्च, 96 की स्थिति)
24.	उत्तर प्रदेश	112566	86250 (*)	26316
25.	पश्चिम बंगाल	38024	29205 (*)	8819
	जोड़	578009	499811	80927
	संघ राज्य क्षेत्र	1123	1120**	0
	कुल जोड़	579132 (583003)	500931	80927

(**) 100% विद्युतीकृत राज्य, शेष गांव विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं है।

(×) 1971 की जनगणना के अनुसार 4727 गांव थे तथा प्रगति 1971 की जनगणना के अनुसार दी जा रही है।

* प्रगति फरवरी, 1996 तक।

· बिना जनगणना वाले गांव सम्मिलित है, आंकड़ों का समाधान किया जा रहा है।

Cellular Phones in Bangalore

40. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) by when the Cellular phones are likely to be introduced in Bangalore;

(b) the reasons for the delay in introducing Cellular phones in Bangalore; and

(c) whether any licence has been given to operate Cellular phones in Bangalore?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) The Cellular Mobile Phone Service in Bangalore is likely to be introduced in the year 1997.

(b) No, Sir, there is no delay in introducing Cellular Mobile Telephone Service in Bangalore.

(c) No, Sir. The letters of Intent have been given to M/s. Modicom Networks Pvt. Ltd. and Ms. J.T. Mobiles Ltd. to operate Cellular Mobile Telephone Service in Karnataka Telecom Circle including Bangalore. The letters of Intent are yet to be converted into licences.

Restructuring the ONGC

41. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to split the Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) into six independent companies, with the Oil and Natural Gas Corporation Limited as holding company; and

(b) if so, the rationale behind this restructuring?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) There is no such proposal under